दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

मई (संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

छत्तीसगढ़ **3**

- मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना 3
- 'मितान योजना' 3
- छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् के महत्त्वपूर्ण निर्णय 3
- माटी पूजन महाभियान 4
- वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक 5
- गोधन न्याय योजना 5
- मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर 6
- निजात अभियान 6
- फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट 6
- बस्तर में रेशम मिशन के तहत रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी 7
- छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडार का भू-तकनीकी मूल्यांकन परियोजना के लिये हुआ एमओयू 7
- उच्च न्यायालय ने झीरम हत्याकांड की न्यायिक जाँच पर रोक लगाई 8
- आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये मिला पुरस्कार 8
- कृषि मंत्री ने बेमेतरा में किया सी-मार्ट का शुभारंभ 9
- खाद्य मंत्री ने किया बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन 9
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्रों में 'अंग्रेज़ी' में अधिसूचित जाति को मान्य किया जाएगा 9
- मुख्यमंत्री ने सुकमा 'सी-मार्ट'का किया लोकार्पण 10
- मुख्यमंत्री ने शुरू किया भेंट-मुलाकात अभियान का दूसरा चरण 11
- बस्तर संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय समझौते 11
- मुख्यमंत्री ने बीजापुर में ज्ञान गुड़ी एजुकेशन सिटी का किया लोकार्पण 12
- मुख्यमंत्री ने बीजापुर में सी-मार्ट का किया लोकार्पण 12
- मुख्यमंत्री ने जैव-विविधता पर केंद्रित दो लघु वृत्तचित्रों का लोकार्पण तथा विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया 13
- मुख्यमंत्री ने जैव-विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं को किया पुरस्कृत 13
- राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन 14
- दंतेवाड़ा ज़िले के बारसूर में राज्य का पहला मॉडल हाट-बाज़ार शुरू 14
- मुख्यमंत्री ने डेनेक्स की नई यूनिट का शुभारंभ किया 15
- 'भगिनी प्रसूति सहायता योजना'का नाम अब 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' 15
- बेहराडीह में खुला प्रदेश का पहला किसान स्कूल 16
- मुख्यमंत्री ने माँ दंतेश्वरी को अर्पित की 11 किमी. लंबी चुनरी 16
- प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ 16
- झीरम घाटी शहीद मेमोरियल 17
- छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता-पत्र देने वाला दूसरा राज्य 17
- छत्तीसगढ़ का पहला फीफा एप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबाल ग्राउंड 18
- आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिये मिला इनोवेशन अवार्ड 18
- राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन 19
- टाटामारी में टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ 19
- राज्य में जारी होंगे पॉलीकार्बोनेट आधारित कार्ड पर क्यूआर कोडयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र 19

नोट :

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिये मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना में बुज़ुर्ग श्रमिकों को एकमुश्त 10 हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के लिये ऐसे श्रमिक पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिये।

'मितान योजना'

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'मितान योजना' का शुभारंभ किया। इसके तहत नागरिक सेवाएँ घर तक पहुँचाई जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में शुरू किया गया है। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।
- वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी और अन्य सेवाएँ भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।
- योजना के तहत लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुँच सुविधा प्राप्त होगी।
- मितान योजना की सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी। सेवाओं हेतु लोगों को मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा।
- इस योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया और आसान होगी। सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषत: बुज़ुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएँ मिल सकेंगी।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद् के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

1 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद् ने 1 नवंबर, 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10 प्रतिशत की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल, 2022 से सामाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन के न्यूनतम 12 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई।

नोट :

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से अंग्रेज़ी में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण-पत्रों में अंग्रेज़ी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के शुल्क माफ करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।
- 'राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मज़दूर न्याय योजना' में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर प्रदाय सहायता राशि 6 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 7 हज़ार रुपए तथा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के देवस्थलों पर पूजा करने वाले बैगा, गुनिया, पुजारी, देवस्थल के हाट पाहार्या एवं बाजा मोहरिया को भी इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि योजना, 2022 प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2002 (यथा संशोधित, 2022) में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन के प्रस्ताव तथा छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों के लिये रियायती दर पर होटल बार लाइसेंस प्रदान किये जाने के निर्णय के साथ ही स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि की दृष्टि से छत्तीसगढ़ टूरिज़्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिये जाने का निर्णय लिया गया।
- आदिवासियों की स्वयं की भूमि में वृक्ष कटाई की प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) संशोधन विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मिट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन हेतु रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के बदले वर्मी कंपोस्ट खाद के उपयोग के साथ गौ-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस वर्ष अक्षय तृतीया 3 मई, 2022 से प्रदेश में माटी पूजन महाअभियान का शुभारंभ करने का निर्णय लिया गया।
- दुर्ग-भिलाई औद्योगिक क्षेत्र में सिटी बस प्रारंभ किये जाने एवं नवीन मार्गों के प्रकाशन के संबंध में परिवहन मंत्री को अधिकृत किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

माटी पूजन महाभियान

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की माटी पूजन की परंपरा के अनुसार छत्तीसगढ़िया किसान की पारंपरिक वेश-भूषा में धोती-कुर्ता पहनकर माटी पूजन किया और धान बुवाई की रस्म अदा कर छत्तीसगढ़ में माटी पूजन महाभियान का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अक्ती तिहार (अक्षय तृतीया) एवं माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी संभाग में यांत्रिकी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी की।
- उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद कृषि महाविद्यालय इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भवन का लोकार्पण किया।
- मुख्यमंत्री ने सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिये डॉप्लर तकनीक का शिलान्यास तथा कृषि विश्वविद्यालय की ओर से विकसित किये गए कृषि रोज़गार मोबाइल एप्लिकेशन का लोकार्पण भी किया।
- मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील कृषकों को सम्मानित किया, साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत बीज किट, कृषि यंत्र और अनुदान राशि का चेक भी प्रदान किया गया।

नोट :

वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक

चर्चा में क्यों ?

3 मई, 2022 को ग्रीस के हेराक्लिओन में चल रहे वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में छत्तीसगढ़ की उदीयमान वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 156 किग्रा. वजन उठाकर रजत पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- राजनांदगाँव की ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किग्रा. भार वर्ग में कुल 156 किग्रा. वज़न उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। इन्होंने 73 किग्रा. स्नैच में और 83 किग्रा. क्लीन एंड जर्क में वज़न उठाया।
- इस वर्ग में भारत की ही रीतिका ने 150 किग्रा. वज़न उठाकर कांस्य पदक प्राप्त किया, वहीं इंडोनेशिया की आयशा कंटिका विंडी ने 185 किग्रा. वज़न उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया।
- उल्लेखनीय है कि ज्ञानेश्वरी जूनियर वर्ग में विश्व चैंपियनशिप खेलने वाली और पदक जीतने वाली प्रदेश की पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले वैश्विक टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ के रूस्तम सारंग, अजयदीप सारंग, अनीता शिंदे, मधुसूदन जंघेल, केशव साहू तथा जगदीश विश्वकर्मा भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन पदक नहीं हासिल कर सके।
- गौरतलब है कि ज्ञानेश्वरी ने 2018-19 में असम के गुवाहाटी स्कूल नेशनल में पहली बार कांस्य पदक जीता था। फिर 2019-20 में स्कूल नेशनल में ही रजत पदक, 2020-21 में राष्ट्रीय यूथ प्रतियोगिता में रजत पदक, 2021-22 में भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में रजत पदक और ऑल इंडिया विवि टूर्नामेंट में भी रजत पदक जीता।

गोधन न्याय योजना

चर्चा में क्यों ?

5 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बलरामपुर ज़िले के राजपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की गई।

प्रमुख बिंदु

- गोधन न्याय योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीद की जा रही है।
- गौठानों में महिला समूहों द्वारा इस योजना के अंतर्गत क्रय किये गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस एवं अन्य उत्पाद तैयार किया जा रहा है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों एवं किसानों को रियायती दर पर प्रदान किया जा रहा है।
- महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियाँ एवं अन्य सामग्री का निर्माण एवं विक्रय कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्ज़ी एवं मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछलीपालन एवं पशुपालन के साथ-साथ अन्य आयमूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।
- गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत उत्पादन की शुरुआत की जा चुकी है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिये एमओयू हो चुका है, साथ ही गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये तेज़ी से कृषि एवं वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं।
- राज्य में गोधन के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये गाँवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का नि:शुल्क बेहतर प्रबंध है। राज्य में अब तक 10,622 गाँवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 8,397 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं।

नोट :

मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर

चर्चा में क्यों ?

6 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर पर किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम अब स्वर्गीय पुनाराम निषाद मात्स्यिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि नवीन मछली नीति निर्माण कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सहमति के उपरांत राज्य शासन द्वारा मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद के नाम पर किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मात्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम छत्तीसगढ़ का एकमात्र मात्स्यिकी महाविद्यालय है, जिसका लोकार्पण 8 जुलाई, 2018 को छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने किया था।
- गौरतलब है कि पद्मश्री स्वर्गीय पुनाराम निषाद छत्तीसगढ़ में महाभारत कथा गायन की लोकप्रिय विधा 'पंडवानी' के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा के बल पर उन्होंने 'पंडवानी' को देश-विदेश में लोकप्रिय बनाया।
- उनकी कला को देखते हुए वर्ष 1974 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें ता

निजात अभियान

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कोरिया और राजनांदगाँव में चलाए जा रहे निजात अभियान को देश भर की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग कार्य प्रणालियों में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- निजात अभियान पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की पहल है, जिसके तहत पुलिस टीम द्वारा शराब, गाँजा और अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री करने वाले कोचियों पर कार्रवाई की गई है।
- इस अभियान के अंतर्गत शहर से लेकर गाँव तक नशे के विरुद्ध लोगों के मध्य व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
- गौरतलब है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने देश भर के स्मार्ट पुलिसिंग के सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों तथा नवाचारों पर एक पुस्तक 'स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्यप्रणालियाँ' प्रकाशित की है।

फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल 'फूड फॉरेस्ट'के अंतर्गत विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के पंद्रह ज़िलों की पहचान की गई है, जहाँ खाद्य वन विकसित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस परियोजना के लिये जिन ज़िलों की पहचान की गई है, उनमें आम की पटी के बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर तथा अमरूद के संभल, रामपुर और बदायूँ आदि शामिल हैं। इसी प्रकार अन्य ज़िलों बुलंदशहर, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतमबुद्ध नगर में भी फल पौधे रोपे जाएंगे।

नोट :

- खाद्य वन में पौधों का चयन कृषि-जलवायु क्षेत्र के अनुसार किया जाएगा। प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिये दलहनी फसलों को भी लगाया जाएगा।
- पूड कोर्ट के माध्यम से सरकार का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है। यह धान-गेहूँ की पारंपरिक खेती की बजाय कृषि विविधीकरण से ही संभव है।
- उदाहरण के लिये गोरखपुर में विकसित होने वाले खाद्य वन के प्रथम चरण में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौधे रोपे जाएंगे। दूसरे चक्र में जामुन, बेर के पौधे रोपे जाएंगे। तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, मटर और चना बोया जाएगा।

बस्तर में रेशम मिशन के तहत रैली कोसा का समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी

चर्चा में क्यों ?

9 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा चालू वर्ष से लघु वनोपज संघ के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोसा कोकून खरीदने का आदेश जारी कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विगत दिवस चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में बस्तर संभाग में रेशम कीट पालन तथा कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासी-वनवासी कृषकों के हित में रेशम मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की थी।
- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बस्तर संभाग में इसके समर्थन मूल्य पर संग्रहण के लिये क्रय दर निर्धारित की गई है।
- शासन के इस महत्त्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा।
- राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोज़गार बढ़ाने हेतु राज्य लघु वनोपज संघ तथा रेशम संचालनालय के बीच एमओयू किया गया है।
- इस एमओयू के अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया गया कोकून रेशम विभाग को प्रदान किया जाएगा।
- रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों का चयन करके उन्हें रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया गया है।
- गौरतलब है कि राज्य में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा-कोकून का उत्पादन होता है। रैली कोसा संग्रहण मुख्य रूप से 7 ज़िला यूनियन जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागाँव, केशकाल, नारायणपुर तथा कांकेर में होता है।

छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडार का भू-तकनीकी मूल्यांकन परियोजना के लिये हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (सीकॉस्ट), रायपुर एवं जवाहरलाल नेहरू एल्युमीनियम अनुसंधान, विकास और अभिकल्प केंद्र (जेएनएआरडीडीसी) खनिज मंत्रालय, भारत सरकार के बीच 'छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट भंडार के भू-तकनीकी मूल्यांकन' परियोजना हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू पर छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् और रीजनल विज्ञान केंद्र के महानिदेशक डॉ. एस. कर्मकार और जेएनएआरडीडीसी के निदेशक डॉ. अनुपम अग्निहोत्री ने हस्ताक्षर किये।
- एमओयू के तहत दोनों संस्थान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से छत्तीसगढ़ में स्थित बॉक्साइट और लैटेराइट भंडार के भू-तकनीकी मूल्यांकन और भू-संदर्भित मानचित्रों का उपयोग कर लैटेराइट और बॉक्साइट भंडारण का ज़िलेवार डिजिटल डेटाबेस तैयार करेंगे।
- अच्छे ग्रेड के कच्चे अयस्क (बॉक्साइट) की कमी का सामना कर रहे एल्यूमिनियम उद्योग और विभिन्न रूपों और प्रक्रियाओं में एल्यूमिनियम का उपयोग करने वाले बॉक्साइट खनिक और उद्योगों के लिये यह परियोजना काफी उपयोगी होगी।

नोट :

- इसका लाभ बॉक्साइट और लैटेराइट अयस्कों का कार्य कर रहे उद्यमियों के अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य भारत में स्थित मौजूदा खान मालिकों और बॉक्साइट उद्योगों को भी मिलेगा।
- राज्य के नए उद्यमी रिमोट सेंसिंग एवं जीआईएस से प्राप्त डेटाबेस का उपयोग किसी भी विद्यमान खनिज, एल्यूमिनियम उद्योग में किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय ने झीरम हत्याकांड की न्यायिक जाँच पर रोक लगाई

चर्चा में क्यों ?

11 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 2013 के झीरम घाटी नक्सली हमले की जाँच के लिये गठित नए न्यायिक आयोग की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायमूर्ति आर.सी.एस. सामंत की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष के नेता धर्मलाल कौशिक द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में झीरम घाटी में 25 मई, 2013 को हुए नक्सली हमले में कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेताओं तत्कालीन कॉन्ग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विपक्ष के पूर्व नेता महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी.सी. शुक्ल सहित 29 लोगों की मौत हुई थी।
- इस हमले की जाँच के लिये 28 मई, 2013 को पूर्व राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया था।
- आठ साल बाद 6 नवंबर, 2021 को झीरम घाटी जाँच आयोग के सचिव और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) संतोष कुमार तिवारी ने राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- राज्यपाल ने इस रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंप दिया था, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने नियमानुसार जाँच रिपोर्ट छह माह के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की और रिपोर्ट को अपूर्ण बताते हुए 11 नवंबर, 2021 को दो-सदस्यीय नए आयोग का गठन किया था।

आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में श्रम विभाग को जनकल्याणकारी योजनाओं के लिये मिला पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2022 को इलेट्स समूह द्वारा आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजन कमेटी की ओर से श्रमिकों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित करने के लिये छत्तीसगढ़ राजभवन के सचिव और श्रम विभाग के सचिव अमृत कुमार खलखो को प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 19-20 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिकों के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएँ संचालित करने के लिये यह पुरस्कार दिया गया था।
- सचिव खलखो ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों के लिये एकीकृत श्रम पंजीकरण प्रणाली लागू की गई है, जिसमें संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिक आवश्यक न्यूनतम दस्तावेज़ों के साथ पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं।
- विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। पहले यह ऑफलाइन था, जिसे अब ऑनलाइन भी किया गया है। पीडीएस डाटाबेस का उपयोग करके श्रमिक पंजीकरण का कार्य किया गया है।
- 148 ब्लॉकों में श्रम संसाधन केंद्र खोले गए हैं। मातृत्व लाभ और सामाजिक योजनाओं के लाभों के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता लाई जा रही है।
- महिला प्रवासी कामगारों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में मदद की जा रही है। बच्चों को उचित औपचारिक शिक्षा देने के लिये श्रम मित्र योजना और शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना चालू की गई है।
- मज़दूरों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता दी जा रही है।

नोट :

कृषि मंत्री ने बेमेतरा में किया सी-मार्ट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

13 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रवींद्र चौबे ने बेमेतरा ज़िला मुख्यालय में सी-मार्ट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित गोठानों में महिला स्व-सहायता समूहों को उनके हाथों से बनाए गए उत्पादों के लिये संगठित बाज़ार उपलब्ध कराने और महिला समूहों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में सी-मार्ट स्टोर्स शुरू किये जा रहे है।
- महिला समूहों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिये प्रथम चरण में ज़िला मुख्यालयों में सी-मार्ट खोले जा रहे हैं, ताकि समूहों के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद वाजिब दाम पर लोगों को उपलब्ध हो सकें।
- सी-मार्ट स्टोर में महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हर्बल साबुन, अचार, मसाले, मुर्रा, दोना-पत्तल, विभिन्न प्रकार के शर्बत, देवभोग के डेयरी प्रोडक्ट, कोरिया की हर्बल चाय, लेमन ग्रास चाय, मशरूम पाउडर, शहद, तेल-गुड़, देसी चना, लाल चावल का पोहा और दूसरी स्थानीय खाद्य सामग्रियाँ भी लोगों के लिये उपलब्ध हैं।
- इसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट इमली, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, शहद जैसे वन उत्पाद की बिक्री की जा रही है।
- सी-मार्ट से हैंडलूम पर बने गमछे और अन्य आकर्षक सूती कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। इसके अलावा बेमेतरा ज़िले के ग्राम राखी में उत्पादित केला तना के रेशे से निर्मित हस्तशिल्प एवं हथकरघा से बने उत्पाद का भी विक्रय किया जाएगा।

खाद्य मंत्री ने किया बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

16 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर ज़िले के मैनपाट विकासखंड की ग्राम पंचायत रोपाखर में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- मैनपाट विकासखंड की ग्राम पंचायत रोपाखर में वन विभाग द्वारा करीब एक करोड़ रुपए की लागत से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है।
- 1-1 हेक्टेयर क्षेत्र में कैक्टस एवं बैंबू पौधे तथा करीब 2 हेक्टेयर में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ निरीक्षण पथ, गार्ड क्वाटर्स सहित अन्य निर्माण कार्य भी कराए जा रहे हैं।
- खाद्य मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने की कड़ी में बायोडायवर्सिटी पार्क भी जुड़ गया है। इस पार्क में पर्यटकों को प्रकृति के विविध रूप देखने को मिलेंगे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्रों में 'अंग्रेज़ी' में अधिसूचित जाति को मान्य किया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

17 मई, 2022 को प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्रों में 'अंग्रेज़ी'में अधिसूचित जाति को मान्य किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा सभी ज़िला कलेक्टरों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 1 मई, 2022 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 'अंग्रेज़ी'में अधिसूचित जाति को मान्य करने तथा जाति प्रमाण-पत्रों में अंग्रेज़ी में ही अधिसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया गया था।

नोट :

- इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों को दूर करना है।
- सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कलेक्टरों को जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 के अधीन बने नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र (जाति प्रमाण-पत्र) जारी किये जाते हैं।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों में हिन्दी में उच्चारणगत विभेद के कारण कतिपय जातियों के जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं।
- पत्र में कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 24 सितंबर, 2013 के संदर्भित परिपत्र में उल्लेख है कि विशेष परिस्थिति में किसी आवेदक को अंग्रेज़ी में जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। अत: सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा यदि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप अनुसार अथवा अंग्रेज़ी में सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी करने की मांग की जाती है तो समुचित जाँच एवं प्रक्रिया अपनाने के उपरांत उसे इस प्रारूप में स्थाई सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।
- इस परिपत्र में दिये गए निर्देश के अनुक्रम में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये हिन्दी, अंग्रेज़ी में अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जाति नामों की सूची प्रकाशित की गई है।
- इस प्रकाशित सूची में अंग्रेज़ी उच्चारण में किसी भी प्रकार की भ्रांति या विवाद नहीं है, अत: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्रों में 'अंग्रेज़ी'में अधिसूचित जाति का उल्लेख किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सुकमा 'सी-मार्ट'का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के द्वितीय चरण में सुकमा ज़िला मुख्यालय में 58 लाख की लागत से निर्मित सी-मार्ट (छत्तीसगढ़ मार्ट) का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने मार्ट से कोदो, कुटकी, रागी, सुगंधित चावल, तीखुर, मसाले का आदि का क्रय कर मार्ट की बोहनी कराई और 1348 रुपए मूल्य के उत्पादों की खरीदी कर वे सुकमा 'सी-मार्ट'के फर्स्ट कस्टमर बने।
- सुकमा सी-मार्ट में ज़िले में कार्यरत 35 स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय उत्पाद, जैसे- शबरी मसाले, शबरी फूड्स, महुआ, काजू, कॉस्मेटिक, साबुन, फिनॉइल, हाइजीन प्रोडक्ट्स, जैसे- सेनेटरी नैपकीन आदि, वनोपज से निर्मित उत्पाद जैसे- अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय, मुलेठी और वन औषधि, एलोवेरा, आमला, महुआ लड्डू आदि से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएँ सहित कुल 81 उत्पाद वर्तमान समय में उपलब्ध हैं।
- सुकमा सी-मार्ट का संचालन शक्ति महिला समूह ग्राम संगठन ग्राम रामाराम द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूती प्रदान करने की दिशा में महिला स्व-सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, दस्तकरों, कुंभकारों और अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिये सी-मार्ट की स्थापना की जा रही है।
- सी-मार्ट में गौठानों में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार विभिन्न तरह के उत्पाद समेत गाँवों में बनने वाले अनेक तरह के उत्पाद एक छत के नीचे बिक्री के लिये उपलब्ध होते हैं।
- इससे ग्रामीण स्तर पर रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। सी-मार्ट महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के लिये आत्मनिर्भर बनने की राह में मील का पत्थर साबित होगा। उनसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

नोट :

मुख्यमंत्री ने शुरू किया भेंट-मुलाकात अभियान का दूसरा चरण

चर्चा में क्यों ?

18 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत बस्तर संभाग के कोंटा विधानसभा से की।

प्रमुख बिंदु

- बस्तर संभाग में भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री 18 मई से 2 जून, 2022 तक बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
- मुख्यमंत्री बघेल ने कोंटा के नगर पंचायत परिसर में आम जनता से भेंट-मुलाकात कर शासकीय कार्यक्रमों और योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ली, उनकी समस्याएँ सुनीं और आम जनता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर कोंटा ज़िले की दो उप-तहसीलों जगरगुंडा एवं दोरनापाल को तहसील बनाए जाने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोंटा ब्लॉक के बंडागाँव एवं जगरगुंडा में विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना, कोंटा के 30 बिस्तर वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (अस्पताल) को विस्तारित कर 50 बिस्तर करने, दुब्बाटोटा में खेल मैदान, छत्तीसगढ़ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा पर छत्तीसगढ़ प्रवेश द्वार और एर्राबोर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराए जाने की भी घोषणा की।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिये भेंट-मुलाकात अभियान की शुरुआत 4 मई से की है।
- भेंट-मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री बघेल ने 4 से 11 मई तक सरगुजा संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तीन ज़िलों के विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुँचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली।
- मुख्यमंत्री ने संपर्क-संवाद-समाधान के ध्येय के साथ जहाँ आम जनता से सीधी बात की और उनकी समस्याओं को जानकर उनका त्वरित निराकरण किया, वहीं जनता की मांग पर उन्होंने विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगातें भी दीं।

बस्तर संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय समझौते

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2022 को राज्य शासन की ओर से वनांचल पैकेज के अंतर्गत बस्तर संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु दो त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- पहला समझौता बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुम्हार पारा, बस्तर के साथ कोंडागांव ज़िले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापना के लिये किया गया तथा दूसरा समझौता मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, पुणे (महाराष्ट्र) के साथ बस्तर ज़िले में इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हेतु किया गया।
- समझौते के तहत बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 4 करोड़ रुपए की लागत से कोंडागांव ज़िले में महुआ डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 600 किलोलीटर प्रतिवर्ष होगी।
- इस प्लांट के द्वारा तैयार अधिकांश उत्पाद को अन्य देशों में निर्यात किया जाएगा। इस प्लांट के लगने से बस्तर क्षेत्र में फूड ग्रेड महुआ का उपयोग होगा, जिससे उस क्षेत्र के संग्राहकों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा।
- इसके अलावा मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ज़िला बस्तर के लोहंडीगुड़ा विकासखंड के ग्राम छिन्दगांव में 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- इस प्रसंस्करण केंद्र में इमली का पेस्ट, इमली बीज का पाउडर तथा इमली ब्रिक्स तैयार किये जाएंगे। इस इकाई की वार्षिक क्षमता 4500 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की होगी।
- इस प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना से बस्तर इमली का प्रसंस्करण करते हुए तथा उसके बीज का भी उपयोग करते हुए तैयार उत्पादों को देश के बाहर विदेशों में भी विक्रय किया जाएगा।

नोट :

- इन दोनों प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से स्थानीय लोगों को जहाँ रोज़गार प्राप्त होगा, वहीं इमली एवं महुआ के संग्राहकों को उनकी उपज का समुचित मूल्य मिल सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी काँकेर ज़िले में कोदो, कुटकी एवं रागी के प्रसंस्करण हेतु निजी निवेशक के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया जा चुका है।
- ये समस्त औद्योगिक इकाईयाँ शीघ्र ही उत्पादन प्रारंभ करेंगी, जिससे प्रदेश में उत्पादित लघु वनोपज का प्रसंस्करण प्रदेश के भीतर ही किया जाना संभव हो सकेगा, जिसका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ 13 लाख से अधिक तेंदूपत्ता और वनोपज संग्राहकों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर में ज्ञान गुड़ी एजुकेशन सिटी का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

20 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान बीजापुर में ज्ञान गुड़ी एजुकेशन सिटी का लोकार्पण कर परिसर में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया।

प्रमुख बिंदु

- एजुकेशन सिटी परिसर में संचालित छू लो आसमान कोचिंग सेंटर में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को नीट, जेईई मेंस, एडवांस, बोर्ड एग्जाम आदि एंट्रेंस एग्जाम के लिये निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष जेईई में 3 बच्चे, नीट में 5 बच्चों का चयन हुआ हैं।
- परिसर में लड़कों व लड़कियों के सर्वसुविधायुक्त हॉस्टल स्थित हैं। परिसर में स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न खेल, जैसे- फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाज़ी, स्विमिंग, कबड्डी, जूडो-कराटे, एथलेटिक्स इत्यादि का प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- यहाँ 280 बच्चों की क्षमता है तथा वर्तमान में 90 बच्चे प्रशिक्षणरत् है। 5 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खेल व 2 बच्चे खेलो इंडिया में विजेता रहे।
- समर्थ पुनर्वास केंद्र में बच्चों को टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से सिखाया जाता है। समर्थ में वर्तमान में बीजापुर ज़िले के सभी विकासखंड के 40 बच्चे हैं, जिन्हें शासन द्वारा मुफ्त में भोजन, आवास आदि सभी सुविधाएँ दी जा रही हैं। यहाँ मानसिक, दृष्टिबाधित अन्य दिव्यांग बच्चों को समर्थ के प्रयास से शिक्षित बनाया जा रहा है।
- संवेदी कक्ष में 21 प्रकार की फिजिकल डिसएबिलिटी वाले बच्चे प्रशिक्षणरत् हैं। यहाँ दृष्टिबाधित बच्चों को हाथों व पैरों के स्पर्श से वस्तुओं एवं रंगों की पहचान करने और स्वाद चखकर खाद्य पदार्थों को पहचानने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर में सी-मार्ट का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

19 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के द्वितीय चरण में बीजापुर ज़िला मुख्यालय में 47 लाख 96 हज़ार रुपए की लागत से नवनिर्मित सी-मार्ट का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने प्रदेशव्यापी भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के द्वितीय चरण में पहले दिन 18 मई को सुकमा ज़िला मुख्यालय में 58 लाख की लागत से निर्मित सी-मार्ट का लोकार्पण किया था।
- सी-मार्ट (छत्तीसगढ़-मार्ट) के नाम से संचालित इस सुपर मार्केट में स्थानीय उत्पाद के अलावा दैनिक उपयोगी वस्तुओं का विक्रय बाज़ार से कम दामों में किया जाएगा।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सभी ज़िला मुख्यालय में राज्य के लघु, कुटीर उद्योगों, स्व-सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिये सुपर मार्केट की तर्ज़ पर सी-मार्ट प्रारंभ किये जा रहे हैं।
- सी-मार्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ के लघु, कुटीर उद्योगों और परंपरागत शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों के साथ महिला समूहों, गोठान में निर्मित सामग्री के साथ-साथ वन विभाग के उत्पादों की बिक्री भी की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के नए अवसर बढ़ेंगे।

नोट :

मुख्यमंत्री ने जैव-विविधता पर केंद्रित दो लघु वृत्तचित्रों का लोकार्पण तथा विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित 'परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण' कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जैव-विविधता पर केंद्रित दो लघु वृत्तचित्रों का लोकार्पण तथा विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने मनेंद्रगढ़ वनमंडल द्वारा तैयार किये जा रहे मैरिन फॉसिल्स पार्क पर आधारित फिल्म 'छत्तीसगढ़ में जीवन चिह्न: मानव अस्तित्व के परे' तथा राज्य के वनक्षेत्रों में पाए जाने वाले शैलचित्रों (केव पेंटिंग्स) पर आधारित फिल्म 'प्रथम अभिव्यक्ति' का लोकार्पण किया।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की जैव-विविधता पर विभिन्न लेखकों की 6 पुस्तकों का विमोचन किया।
- मुख्यमंत्री ने लेखक डॉ. शिवाजी चवन की पुस्तक 'छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, 2022-30', भारतीय वन सेवा के अधिकारी रामकृष्णा की गुरु घासीदास टाइगर रिज़र्व में गुफा शैलचित्रों पर केंद्रित पुस्तक 'शेड्स ऑफ पास्ट', गौरव निहलानी तथा ज्ञानेंद्र पांडेय वसुंधरा प्राकृतिक संरक्षण समिति की पुस्तक 'छत्तीसगढ़ में ईको पर्यटन - संभावनाएँ एवं चुनौतियां' का विमोचन किया।
- इसी तरह उन्होंने शैलेंद्र उईके और भारतीय वन सेवा के श्रीनिवास टी. की पुस्तक 'अ फिल्ड गाइड टू फॉरेस्ट ग्रासेस ऑफ छत्तीसगढ़', डॉ. विवेक कुमार सिंघल तथा डॉ. हेमकांत चंद्रवंशी अंकित सेवा संस्थान की पुस्तक 'बायोडायवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ूस स्वाइल' तथा 'इनसेक्ट बायोडायवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़' का भी विमोचन किया।
- गौरतलब है कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव-विविधता के मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन को विश्व जैव-विविधता दिवस के रूप में भी जाना जाता है।

मुख्यमंत्री ने जैव-विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं को किया पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित 'परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण' कार्यक्रम में जैव-विविधता के संरक्षण और संवर्द्धन के लिये व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में जैव-विविधता, पालतू पशुओं के संरक्षण, जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, व्यक्तियों एवं जैव प्रबंधन समितियों के लिये पुरस्कार घोषित किये। कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े वनमंडलाधिकारियों द्वारा संबंधित व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया।
- ये पुरस्कार वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं पालतू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग, सभ्यता, संस्कृति एवं धरोहर से जैव-विविधता संरक्षण तथा श्रेष्ठ जैव-विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणियों में दिये गए।
- छत्तीसगढ़ जैव-विविधता पुरस्कार, 2022 के तहत श्रेष्ठ संस्थान श्रेणी में श्रेष्ठ जैव-विविधता प्रबंधन समिति शाहवाड़ा, कांकेर और प्रबंधन समिति चीचा दुर्ग को 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
- इसी प्रकार जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग व्यक्तिगत श्रेणी में किशोर कुमार राजपूत तथा पालतू प्रजातियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में डॉ. पदम जैन को 25 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र-प्रदान कर सम्मानित किया गया।
- पालतू प्रजातियों का संरक्षण संस्था श्रेणी में पीपुल फॉर एनिमल दुर्ग-भिलाई यूनिट-2 तथा वन्य प्राणियों का संरक्षण संस्था श्रेणी में नेचर बायोडायवर्सिटी एसोसिएशन को 50 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति-पत्र और वन्य प्राणियों का संरक्षण व्यक्तिगत श्रेणी में राजेंद्र प्रसाद मिश्र और सुश्री निधि तिवारी को प्रशस्ति-पत्र एवं 25 हज़ार रुपए की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया।

नोट :

राज्य कैंसर संस्थान का वर्चुअल भूमि पूजन

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक 'राज्य कैंसर संस्थान'का भूमि-पूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य कैंसर संस्थान कैंसर के इलाज के लिये आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होगा और आगामी एक वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
- बिलासपुर में निर्मित होने वाले राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होगी।
- राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार की कीमोथेरैपी, जैसे- टार्गेटेड, इम्यूनो, मॉलिकुलर, मेटरोनॉमिक सुविधा नि:शुल्क मिलेगी। यहाँ अत्याधुनिक रेडियोथेरैपी मशीन से इलाज किया जाएगा।
- दो लीनियर एक्सीलरेटर, कोबाल्ट ब्रेकीथेरेपी यूनिट, पीईटी स्कैन मशीन, सीटी सिमुलेटर, एमआरआई मशीन और कैंसर अनुसंधान के लिये सभी अत्याधुनिक साधन राज्य कैंसर संस्थान में उपलब्ध होंगे।
- स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, मुख एवं गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, बड़ी आँत एवं गुदा का कैंसर, पेट के कैंसर, यकृत, पित्त की थैली के कैंसर, हड्डी के कैंसर, ब्लड कैंसर का इलाज एक ही छत के नीचे हो सकेगा।

दंतेवाड़ा ज़िले के बारसूर में राज्य का पहला मॉडल हाट-बाज़ार शुरू

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री-एक्ज़िट द्वार वाला मॉडल हाट-बाज़ार दंतेवाड़ा ज़िले के गीदम विकासखंड अंतर्गत बारसूर में शुरू किया गया।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस मॉडल हाट-बाज़ार का निर्माण किया गया है।
- पहली बार हाट-बाज़ार में एंट्री और एक्ज़िट हेतु सुनियोजित द्वार बनाए गए हैं, जहाँ ग्रामीणों या व्यापारियों द्वारा लाए गए सामान या उत्पाद को वज़न किया जाता है, जिससे ग्रामीण निर्धारित कीमत पर सामान का विक्रय कर सकें।
- इसके साथ ही एक्ज़िट द्वार पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें उनके सामानों का उचित मूल्य प्राप्त हुआ है या नहीं।
- मॉडल हाट-बाज़ार होने से छोटे व्यापारियों के लिये वज़न मशीन द्वारा लाए गए सामानों की वज़न कर स्थानीय बोली में बताया जाता है।
- हाट-बाज़ार में ही खाद्य सामाग्री को सुरक्षित रखने हेतु ड्राई व कोल्ड स्टोरेड की सुविधा दी गई है, ताकि बिक्री के बाद बची हुई सामग्री को अगले बाज़ार तक सुरक्षित रखा जा सके।
- मॉडल हाट-बाज़ार से लगभग 200 व्यापारियों को लाभ मिल रहा है। हाट-बाज़ार स्थल पर ही मुख्यमंत्री हाट-बाज़ार क्लीनिक योजना का संचालन भी किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि बस्तर अंचल में हाट-बाज़ार का अपना एक अलग ही महत्त्व है। हाट-बाज़ार को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माना जाता है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने डेनेक्स की नई यूनिट का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा ज़िले के कटेकल्याण में अपनी टेक्सटाइल यूनिट की वजह से देश भर में चर्चित दंतेवाड़ा के नवाचार डेनेक्स की नई यूनिट का शुभारंभ किया। यहाँ 100 महिलाएँ गारमेंट्स बनाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- इसी के साथ डेनेक्स की पाँचवी यूनिट छिंदनार का एमओयू हुआ। यह एमओयू डेनेक्स एफपीओ (किसान उत्पादक संघ) और एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर के बीच हुआ, जो तमिलनाडु के कोयंबटूर में होल सेल की देश की सबसे बड़ी यूनिट में से एक है।
- अभी तक स्थापित डेनेक्स की चार यूनिट हारम, बारसूर, कारली, कटेकल्याण से कपडों की लाट बंगलूरू भेजी जा रही थी, लेकिन इस एमओयू के बाद डेनेक्स की पाँचवीं यूनिट छिंदनार से तैयार होने वाले कपड़े यूके और यूएस के बाज़ार में भी नज़र आएंगे।
- उल्लेखनीय है कि डेनेक्स के माध्यम से दंतेवाड़ा वस्त्र व्यवसाय के एक नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। यहाँ के कपड़ों की गुणवत्ता की वजह से देश भर में इनकी मांग बढ़ी है और देश भर की व्यापारिक संस्थाएँ इनसे एप्रोच कर रही हैं।
- अब से लगभग 16 महीने पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य दंतेवाड़ा ज़िले में महिलाओं की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिये ज़िला प्रशासन ने ग्राम पंचायत हारम में नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहाँ बने कपड़ों को ब्रांड नाम दिया गया 'डेनेक्स'। डेनेक्स का अर्थ है 'दंतेवाड़ा नेक्स्ट'। इस ब्रांड में दंतेवाड़ा ज़िले की समृद्धि, परंपरा एवं संस्कृति की झलक दिखाई देती है।
- बीते 16 माह में ही डेनेक्स की चार यूनिट से लगभग 50 करोड़ रुपए मूल्य की 6 लाख 85 हज़ार कपड़ों की लॉट बंगलूरू भेजी जा चुकी है, जहाँ से इनका विक्रय पूरे देश में (कश्मीर से कन्याकुमारी तक) हो रहा है। डेनेक्स से दंतेवाड़ा के लगभग 800 लोगों को रोज़गार मिला है।
- डेनेक्स की यूनिटों के तेज़ी से प्रसारित होने की वजह से न केवल महिलाओं को रोज़गार मिला है, अपितु देश भर में संस्थान के कपड़ों की डिमांड होने से अपने कौशल संवर्धन का कार्य भी हो रहा है।
- गौरतलब है कि डेनेक्स की महिलाओं ने हाल ही में ग्यारह किमी. लंबी चुनरी का निर्माण किया है, जिसे मुख्यमंत्री दंतेश्वरी माता को अर्पित करेंगे।

'भगिनी प्रसूति सहायता योजना'का नाम अब 'मिनीमाता महतारी जतन योजना'

चर्चा में क्यों ?

23 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिये संचालित 'भगिनी प्रसूति सहायता योजना'में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए अब इस योजना का नाम 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 'भगिनी प्रसूति सहायता योजना'को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के असंगठित क्षेत्रों के कमज़ोर आय वर्ग की श्रमिक महिलाओं को प्रसूति के लिये आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करना है।
- इसके लिये गर्भधारण के बाद से प्रसूति तक महिलाओं को उचित व भरपूर आहार हेतु सहायता राशि प्रदान की जाती है, इससे महिलाओं व बच्चे के शरीर को गर्भावस्था में आहार व पोषण की कमी और आर्थिक समस्या नहीं होती।
- योजना के तहत 10000/- रुपए प्रसूति लाभ दिया जाता है, जिसमें से 5000/- रुपए गर्भधारण के प्रथम तिमाही में एवं शेष 5000/- रुपए तृतीय तिमाही (आठवें माह) में दिये जाते हैं। सहायता राशि का भुगतान सूचनाप्राप्ति के 72 घंटे के भीतर कर दिया जाता है।
- योजना में शामिल होने के लिये पात्रता-
- हितग्राही के पति या पत्नी का पंजीयन आवश्यक।
- महिला श्रमिक के गर्भधारण का अधिकृत सत्यापन डॉक्टर, एएनएम अथवा मितानीन के द्वारा होना अनिवार्य।

नोट :

- सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थानों में कार्य कर रहे निर्माण श्रमिक की पत्नी को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- प्रसूति योजना का लाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा।
- लाभ की पात्रता पंजीयन के 90 दिवस के उपरांत।

बेहराडीह में खुला प्रदेश का पहला किसान स्कूल

चर्चा में क्यों ?

22 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने जांजगीर-चांपा ज़िले के बलौदा ब्लॉक के ग्राम बहेराडीह में प्रदेश के पहले किसान स्कूल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. चरणदास महंत ने इस अवसर पर कहा कि यह स्कूल देश में अपनी तरह का पहला स्कूल है, जहाँ किसानों को खेती के संबंध में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इस स्कूल में किसानों को कृषि क्षेत्र में 18 अलग-अलग विषयों में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरह की जानकारी मिलेगी।
- इस स्कूल में किसानों को कृषि क्षेत्र में खरीफ फसल, रबी फसल के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, मछली पालन, लाख उत्पादन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, सब्जी खेती प्रबंधन, कोसा कीट पालन व अन्य विषयों की जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने माँ दंतेश्वरी को अर्पित की 11 किमी. लंबी चुनरी

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान दंतेवाड़ा ज़िले में माँ दंतेश्वरी का दर्शन कर उन्हें डेनेक्स की महिलाओं द्वारा तैयार की गई 11 किमी. लंबी चुनरी ओढ़ाई, जिससे इन महिलाओं का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि डेनेक्स (दंतेवाड़ा नेक्स्ट) की 300 महिलाओं ने केवल 7 दिनों में अपने हुनर से 11 किमी. लंबी यह चुनरी तैयार की है।
- इससे पहले भी डेनेक्स में काम करने वाली महिलाएँ 8,000 मीटर लंबी चुनरी बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित कर चुकी हैं। इस चुनरी को 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में नर्मदा नदी पर चढ़ाया गया था।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर में पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर में मावली माता और भैरव जी के दर्शन भी किये।
- इस दौरान मंदिर परिसर में पारंपरिक वाद्ययंत्रों की सुमधुर ध्वनि से पूरा वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया था।
- ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि डेनेक्स की महिलाओं ने जो चुनरी बनाई है, उससे उनके हुनर को पूरे देश में जगह मिलेगी और इससे उनके काम की ख्याति दुनिया भर में फैलेगी।
- गौरतलब है कि 'दंतेवाड़ा नेक्स्ट' (डेनेक्स) एक कपड़ा निर्माता कंपनी है, जिसे ज़िला प्रशासन ने जनवरी 2021 में शुरू किया था। वर्तमान में ज़िले में इसकी पाँच इकाईयाँ हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

24 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सुदूर अंचल दंतेवाड़ा से राज्य के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा एवं उद्यानिकी फसलों की मौसम आधारित बीमा दावा राशि के वितरण का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- रबी एवं उद्यानिकी फसलों की बीमा योजना के तहत राज्य के 17 ज़िलों के लगभग डेढ़ लाख किसानों को 307 करोड़ 19 लाख रुपए की दावा राशि मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने किसानों को फसल बीमा दावा राशि के भुगतान में विलंब न हो, इसके मद्देनज़र राजधानी रायपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बजाय दंतेवाड़ा से ही ऑनलाइन शुभारंभ किया। इससे पूर्व गोधन न्याय योजना की राशि का वितरण उन्होंने सरगुजा संभाग में भेंट-मुलाकात अभियान के दौरान रामानुजगंज से किया था।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत राज्य के 17 ज़िलों के लगभग 1 लाख 45 हज़ार किसानों को 297 करोड़ 9 लाख रुपए तथा उद्यानिकी फसलों के मौसम आधारित बीमा योजना के अंतर्गत 4,747 कृषकों को 10 करोड़ 10 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। खरीफ 2021 में राज्य के 3 लाख 97 हज़ार कृषकों को 752 करोड़ रुपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है।
- कृषि मंत्री रवींद्र चौबे ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में सबसे अधिक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने और राज्य के किसानों को इसका लाभ दिलाने में छत्तीसगढ़ देश में पहले नंबर पर है। किसानों को रबी फसलों के बीमा दावा का भुगतान के मामले में भी छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है।
- गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 से लागू है। इसके तहत किसानों को खरीफ फसलों धान, मक्का, मूँगफली, सोयाबीन, अरहर, मूंग और उड़द के लिये मात्र 2 प्रतिशत तथा रबी फसलों गेहूँ, चना, राई-सरसों एवं अलसी के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होती है। शेष बीमा प्रीमियम राशि का आधा-आधा हिस्सा राज्यांश एवं केंद्रांश होता है।

झीरम घाटी शहीद मेमोरियल

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण किया और झीरम घाटी के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने मेमोरियल परिसर में ही 100 फीट ऊँचे तिरंगे का भी ध्वजारोहण किया, जो शहीदों के सम्मान के रूप में सदैव लहराता रहेगा।
- झीरम घाटी में शहीद 32 लोगों की यादों को आम लोगों के दिलों में सदैव ज़िंदा रखने के लिये जगदलपुर के लागबाग मैदान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया गया है।
- गौरतलब है कि आज से ठीक 9 साल पहले 25 मई, 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कॉन्ग्रेस के वरिष्ठ नेताओं नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा और पुलिस के जवानों सहित 32 लोग शहीद हो गए थे।
- झीरम घाटी में शहीद 32 जनप्रतिनिधियों एवं जवानों की मूर्तियाँ उनके नाम के साथ स्थापित की गई हैं, जो उनकी पहचान को सदैव जीवित रखेंगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में शहीदों के बलिदान की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये 25 मई को झीरम घाटी श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता-पत्र देने वाला दूसरा राज्य

चर्चा में क्यों ?

25 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर विधानसभा के मंगलपुर में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान वनवासियों को नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता-पत्र दिये जाने की घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- ओडिशा के बाद छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य होगा, जो नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता-पत्र प्रदान करेगा।
- वन संसाधन मान्यता-पत्र मिलने से वनवासियों को रोज़गार के साथ-साथ आय के लिये अधिक-से-अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित अन्य घोषणाएँ भी कीं-
- कोटमसर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आदिवासी युवकों को 15 जिप्सी वाहन दिये जाएंगे।
- सुकमा के दोरनापाल, कूकनार और तोंगपाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल आरंभ किये जाएंगे।
- कनकापाल से लेदा और जीरम से एलमनार तक सड़क बनाई जाएगी।
- मावलीपदर, नेतानार, पंडरीपानी और माड़पाल में आदर्श देवगुड़ी की स्थापना की जाएगी।

छत्तीसगढ़ का पहला फीफा एप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबाल ग्राउंड

चर्चा में क्यों ?

26 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में छत्तीसगढ़ के पहले फीफा एप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबाल ग्राउंड और रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- जगदलपुर प्रियदर्शिनी इंदिरा स्टेडियम के फुटबाल मैदान को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण-पत्र जारी किया है।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रियदर्शिनी स्टेडियम में 44 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक राशि के 19 विकास कार्यों का लोकार्पण और 11 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक राशि के 8 विकास कार्यों का शिलान्यास किया।
- बस्तर में ग्रास रूट लेबल पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये ओडिशा भुवनेश्वर की आर्डोर फुटबाल अकादमी, बस्तर ज़िला फुटबाल संघ तथा बस्तर ज़िला प्रशासन के बीच एमओयू किया गया। इससे बस्तर के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे।

आत्मनिर्भर भारत समिट में डिजिटल गवर्नेंस के लिये मिला इनोवेशन अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

27 मई, 2022 को आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस के लिये इलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को यह अवार्ड 'एनजीओ पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने और मान्यता और अनुदान' की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिये दिया गया है।
- इलेट्स टेक्नो इंडिया के सीईओ डॉ. रवि गुप्ता ने यह अवार्ड छत्तीसगढ़ राज्य के समाज कल्याण विभाग के संचालक पी. दयानंद को प्रदान किया।
- समाज कल्याण विभाग के संचालक पी. दयानंद ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने ज़रूरतमंदों की मदद के लिये हर संभव प्रयास किया। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ में एनजीओ मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से सहायता पहुँचाई जा सकी।
- विभाग द्वारा एनजीओ मान्यता और अनुदान के लिये आवेदन की मैन्युअल प्रक्रिया को डिजिटल में बदलते हुए पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।
- विभाग ने अटैचमेंट के साथ सभी आवश्यक डेटा को अनुकूलित तरीके से संधारित किया है, जिसे हितधारक एनजीओ, डीडीओ, कलेक्टर, निदेशालय, सचिवालय और मंत्री सभी उपयोगकर्त्ता देख सकते हैं।

नोट :

राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिये विशेषज्ञ समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

27 मई, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मा. न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता इस विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।
- इसके अलावा समिति में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्ता मनु गौड़ और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
- समिति के गठन को लेकर राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जाँच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन के साथ उस पर रिपोर्ट करने के लिये इस समिति का गठन किया जा रहा है।
- इसके अलावा विवाह, तलाक, संपत्ति के अधिकार, उत्तराधिकार से संबंधित लागू कानून और विरासत, गोद लेने और रख-रखाव और सरंक्षता इत्यादि एवं समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल की स्वीकृति से विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा है।

टाटामारी में टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व-सहायता समूह की बहनों ने कोंडागाँव ज़िले में पर्यटन सुविधाओं की जानकारी देने के लिये टाटामारी में निर्मित टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- टाटामारी के बिहान कैंटीन में कार्यरत महिला समूह की अध्यक्ष लक्ष्मी साहू एवं सदस्य जयंती ध्रुव के हाथों मुख्यमंत्री ने टाटामारी के इस सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ कराया।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा इस सेंटर का निर्माण लगभग 25.36 लाख रुपए की लागत से किया गया है। इस टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र भी बनाया गया है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मावा कोंडानार पर्यटन सर्किट पर केंद्रित पुस्तिका और लोगो का विमोचन किया।
- गौरतलब है कि कोंडागाँव ज़िले में अपार पर्यटन की संभावनाओं के दोहन और स्थानीय लोगों को रोज़गार दिलाने के उद्देश्य से मावा कोंडानार पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है।
- इसके लिये 3 दिन एवं 2 रातों का पर्यटन पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें पर्यटक स्थानीय प्रकृति के सान्निध्य में मनोरम वादियों, 20 से अधिक जलप्रपातों, पुरातात्त्विक अवशेषों, आदिवासी सभ्यता-संस्कृति, प्रागैतिहासिक शैलचित्रों, कोंडागाँव की अनोखी संस्कृति से परिचित हो सकेंगे।

राज्य में जारी होंगे पॉलीकार्बोनेट आधारित कार्ड पर क्यूआर कोडयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

29 मई, 2022 को सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' को और सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में अब प्रदेश में जारी होने वाले समस्त 'ड्राइविंग लाइसेंस' एवं 'पंजीयन प्रमाण-पत्र' पॉलीकार्बोनेट आधारित कार्ड पर एवं क्यूआर कोडयुक्त होंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि भारत सरकार के भूतल एवं परिवहन विभाग (MoRTH) द्वारा वर्ष 2019 में जारी अध्यादेश के अनुपालन में एकीकृत ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किया जाना है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने हाल ही में निविदा प्रक्रिया संपन्न की है एवं यह योजना 17 मई, 2022 से प्रादेशिक स्तर पर प्रारंभ की गई है।
- ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रिंटिंग का कार्य 'केंद्रीकृत कार्ड प्रिंटिंग एवं डिस्पैच यूनिट' पंडरी रायपुर में किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ सरकार की संकल्पित योजना के अंतर्गत भारतीय डाक के माध्यम से आवेदकों के घर पर प्रेषित किये जाएंगे।
- इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत 'क्यूआर कोड' वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी किये जाएंगे। पॉलीकार्बोनेट कार्ड उच्च गुणवत्ता एवं लंबे समय तक चलने वाले होते हैं, जिस पर लेजर के माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। यह कार्ड सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली (MoRTH) के द्वारा तय मानकों को पूर्ण करते हुए जारी किये जाएंगे।
- नए प्रारूप के 'क्यूआर कोड' वाले पॉलीकार्बोनेट ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र के प्रिंटिंग का कार्य 'एमसीटी काड्र्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा कार्य किया जाएगा। यह कंपनी मनिपाल कर्नाटका की आईटी कंपनी है, जो कि इस क्षेत्र में अग्रणी है एवं इसी प्रकार के कार्य अन्य राज्यों में करती आ रही है।
- परिवहन विभाग द्वारा संचालित 'तुंहर सरकार तुंहर द्वार' योजना लोगों की सुविधा के लिये अतिमहत्त्वपूर्ण योजना है। परिवहन विभाग से संबंधित जनसुविधाएँ इतनी सहजता से घर बैठे मिलने से लोगों को अब बार-बार परिवहन विभाग के चक्कर लगाने की आवश्कयता नहीं पड़ती। इसके चलते आवेदकों के समय और धन की बचत होगी।

The Vision

नोट :